जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

उदयपुर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 29 संख्याः 316 प्रभात उदयपुर, रविवार 18 सितम्बर, 2022 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

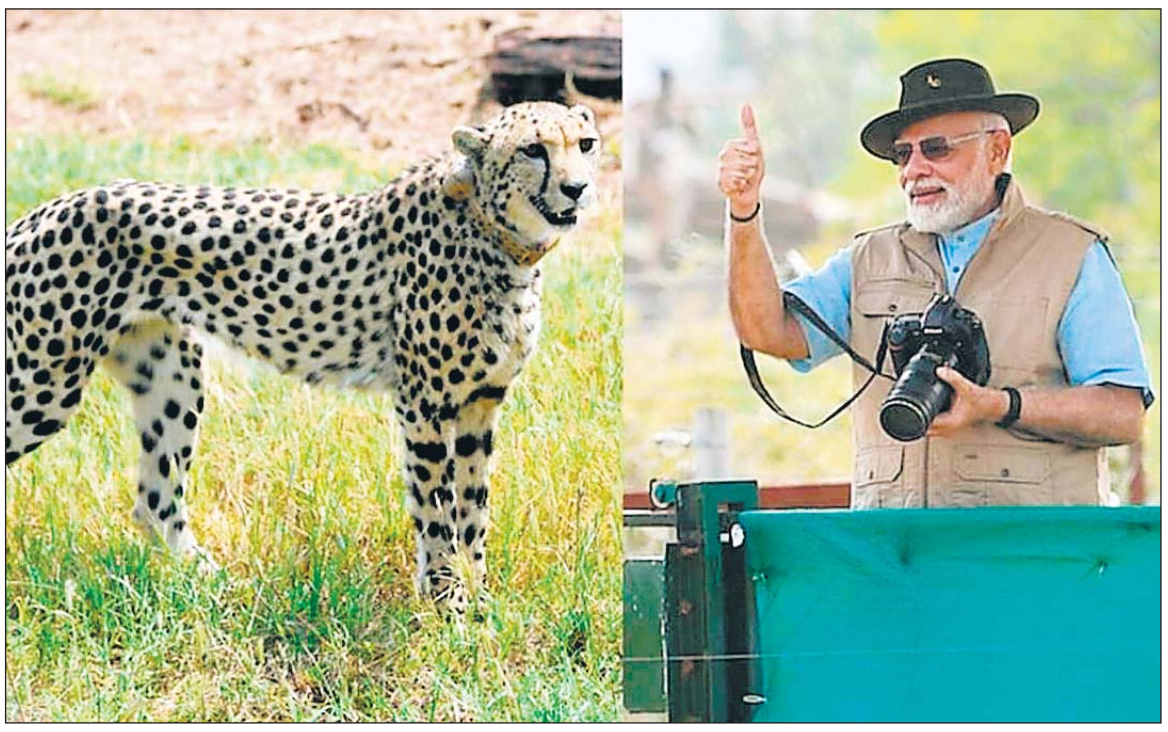

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आए चीतों को मध्यप्रदेश के कूनो नैशनल पार्क में छोड़कर लगभग 70 वर्षों बाद देश में फिर से चीता बसाने की महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की। नामीबिया से पहले चरण में आठ चीते विशेष विमान से मध्यप्रदेश लाए गए, जिनमें पांच मादा और तीन नर हैं। केन्द्र सरकार की देश में चीतों को फिर से बड़े पैमाने पर बसाने की योजना के तहत सबसे पहले कूनो नैशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल इन चीतों को वन्यजीव विशेषज्ञों की देखरेख में रखा गया है, ये लोग चीतों की प्रत्येक गतिविधि पर बारीकी से नजर रखेंगे। लगभग पांच घंटों की मध्यप्रदेश यात्रा के दौरान मोदी ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के लिए बनाए गए विशेष बाड़े के पास बनी मचान पर खड़े होकर दो विशेष पिंजरे खोले, जिसके साथ ही चीते बाहर निकलकर बाड़े में विचरण करने लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में मोदी ने चीतों को विचरण करते हुए न सिर्फ काफी नजदीक से देखा, बल्कि इन ऐतिहासिक क्षणों को अपने कैमरे में कैद भी किया। मोदी ने राष्ट्रीय उद्यान में ही चीता मित्रों से संवाद किया। राष्ट्रीय उद्यान के कारण विस्थापित ग्रामीणों में से कुछ का चयन कर उन्हें चीता मित्र बनाया गया है, जो चीतों की सुरक्षा का कार्य देखेंगे। इसके अलावा उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्र. मंत्री मोदी ने चीतों को पार्क में छोड़ने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए चीतों की सुरक्षा का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि, देश में 70 सालों के बाद चीते बसाने का कार्य हो रहा है और देश के साथ ही मध्यप्रदेश के लोगों ने हमेशा उनका भरोसा कायम रखा है। इसलिए सब लोग चीतों की सुरक्षा का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि "विदेश से आए चीतों को अभी अपना घर बनाना है। इसलिए लोगों को चीतों को देखने के लिए धैर्य रखना होगा। अभी ये चीते क्षेत्र से अनजान हैं। इसलिए उन्हें कुछ महीनों का समय देना होगा।"

अब निगाह इस पर टिकी है, कब सोनिया गांधी गहलोत को दिल्ली बुलाती हैं

यह माना जा रहा है कि, सोनिया गांधी, गहलोत से मु.मंत्री पद से इस्तीफा ले लेंगी और तब गहलोत से कांग्रेसाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव का पर्चा दाखिल करवायेंगी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। इस समय सभी लोगों की नज़रें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिकी हुई हैं कि वे अशोक गहलोत को मिलने के लिये कब बुलाती हैं। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि वे अशोक गहलोत को, पार्टी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरने से पहले, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिये कह सकती हैं ताकि नये मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर रास्ता साफ हो सके तथा पार्टी नेतृत्व इसके लिए पर्यवेक्षक भेजे तथा वह सारी कवायद हो, जो इस प्रकार की प्रक्रियाओं का हिस्सा बन चुका है।

सूत्रों ने कहा कि इस मुद्दे की गहन जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष एवं तथाकथित हाईकमान बन जाने के बाद, सचिन पायलट के नाम के खिलाफ अपने विशेषाधिकार (वीटो) का उपयोग कर सकते हैं तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे मुख्यमंत्री न बनें।

दिल्ली के ज्यादातर राजनैतिक पर्यवेक्षकों तथा नेताओं का गहलोत की इस क्षमता में पूरा विश्वास है कि वे सचिन पायलट का पूरा खेल बिगाड़ते हुये, उन्हें दरकिनार कर दें।

अध्यक्ष पद की नामांकन प्रक्रिया 24 सितम्बर को शुरू होगी तथा उससे पहले ही, राजस्थान कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट हो जाने की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस के कुछ वर्गों का विचार है कि इस समय गांधी परिवार को नेतृत्व अपने पास ही रखने की जरूरत है ताकि वह भाजपा नेतृत्व द्वारा परेशान किये जाने से बचा रहे, जैसा कि नेशनल हैरल्ड केस में ई.डी. द्वारा किया गया था।

- तर्क यह है कि, कांग्रेसाध्यक्ष बनने के बाद गहलोत अपना वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं, सचिन पायलट को मु.मंत्री बनने से रोकने के लिये।
- बहरहाल 24 सितम्बर को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिये पर्चा दाखिल होंगे, तब स्थिति और स्पष्ट हो जायेगी।
- फिलहाल दिल्ली में वरिष्ठ नेता व राजनीतिक ऑब्ज़र्वर अभी भी मानते हैं कि, गहलोत किसी न किसी तरह यह "मैनेज" करने में सफल होंगे कि, पायलट मु.मंत्री न बनें।
- एक तर्क यह है कि, गांधी परिवार कांग्रेस का नेतृत्व अपने पास ही रखना चाहेगा, ताकि भाजपा द्वारा ई.डी. आदि केन्द्रीय एजेंसियों के जरिए पूछताछ के नाम पर लगातार उन्हें तंग करने के प्रयास को विफल किया जा सके।

ज्ञानवापी मस्जिद

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। मुस्लिम समुदाय ने ज्ञानवापी मस्जिद पर दिए गए वाराणसी जिला जज के

- मुस्लिम संगठन अडिग हैं कि, ज्ञानवापी मस्जिद में हिन्दुओं को पूजा नहीं करने दी जाएगी और इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि, इलाहाबाद जिला जज का फैसला 1991 के पूजा स्थल कानून का उल्लंघन है।

12 सितम्बर के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है, वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी में मस्जिद में हिंदुओं को प्रार्थना पूजा का अधिकार दिया है। यही नहीं मुस्लिम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपनी लगातार जीत से चिंतित है यूक्रेन

भय है कि, रूस की लगातार हो रही हार व रूसी सैनिकों की युद्ध में भारी संख्या में हुई मृत्यु से कहीं पुतिन का सब्र न टूट जाये तथा वे युद्ध को और खतरनाक स्तर पर न ले जायें

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। सात माह हो चुके हैं, क्या रूस-यूक्रेन विवाद "तीसरे विश्व युद्ध" के कगार पर है? वैस्टर्न मीडिया की ग्राउण्ड रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस युद्ध में सबसे बड़ी क्षति का अनुभव कर रहा है क्योंकि यूक्रेन की फौजों ने हारी हुई जमीन का अधिकांश हिस्सा पुनः जीत लिया है जिससे रूस की फौज के मनोबल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। कई अज्ञात बीमारियों से पीड़ित राष्ट्रपति पुतिन का धैर्य जवाब दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ैलेन्स्की ने रूस की सेना के विरूद्ध बड़ी दृढ़ता से जवाबी प्रहार किया और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली सुरक्षा गारंटी ने पुतिन को और क्रूद्ध कर दिया है।

मीडिया की खबरें संकेत देती हैं कि रूस की सैन्य विफलता के कारण राष्ट्रपति पुतिन को उस नए विपक्ष से चुनौती मिल सकती है जो यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ है। त्वरित जीत दर्ज ना कर पाने और अब जवाबी हमला होने के कारण रूस अपने कई सैनिकों और सैन्य उपकरणों हथियारों को खो चुका है। इससे रूस के लोगों में भारी गुस्सा है, जिसे पुतिन के विरोधी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं।

स्पेनिश न्यूज़ ऑनलाइन ए.एस. के अनुसार यूक्रेन की सेना देश के दक्षिण और उत्तर में हारी हुई जमीनों पर फिर से कब्जा जमा रही है, लेकिन मॉस्को से एक बड़ा जवाबी हमला होने की आशंकाओं को लेकर चिन्ता है जो कि इस युद्ध के अपेक्षाकृत अधिक नृशंस चरण में आ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ैलेन्स्की और उनकी सरकार ने पश्चिमी देशों से भविष्य का समर्थन सुनिश्चित करने को लेकर नई सुरक्षा गारंटियों के दस्तावेज तैयार किए हैं। जाहिर तौर पर इस दस्तावेज का उद्देश्य आगे होने वाले हमलों के विरूद्ध यूक्रेन की रक्षात्मक क्षमताओं की किलेबंदी करना है, लेकिन ज़ैलेन्स्की द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में और आगे की बात कही गई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इस आशंका को भुनाते हुए यूक्रेन ने अमेरिका व अन्य नाटो राष्ट्रों से और अधिक आधुनिक हथियारों की मांग की है, जिसकी पूर्ति के लिये अमेरिका व यूरोपीय देश लगभग तैयार हैं।
- रूस ने और अधिक हथियार देने के खिलाफ नाटो देशों को चेतावनी व धमकी भी दी है।

डब्ल्यु.एच.ओ. की चेतावनी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यु.एच.ओ.) ने कोविड-19 के लिए असाध्य रोगियों के लिए उपयोग की जाने वाली रैमडेसिविर एंटीवायरल दवा के विरूद्ध कड़ी चेतावनी है।

- वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ने एक शोध के आधार पर कोविड-19 के गंभीर मरीजों में रैमडैसिविर दवा का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी है और कहा है कि, यह दवा ओमक्रॉन पर भी कारगर नहीं है।

इसके इस्तेमाल को लेकर यह कठोर सिफारिश पूर्व सशर्त सिफारिशों का स्थान लेती और यह लैबोरेट्री स्टडीज़ से मिले उस साक्ष्य पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि यह दवा के ओमक्रॉन जैसे वर्तमान प्रसारित वेरिएन्ट्स के विरूद्ध संभवतया असर नहीं करती है। भारत में शनिवार को कोविड-19 के केसों की संख्या कम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

निज़ाम शासन से मुक्ति दिवस या "तेलंगाना इन्टिग्रेशन डे"

अमित शाह व तेलंगाना के मु.मंत्री के.सी.आर. ने कुछ किलोमीटर की दूरी पर अलग-अलग झण्डा रोहण किया, एक ही दिन

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। तेलंगाना की राजधानी, यानी हैदराबाद शहर शनिवार को हॉटस्पॉट बन गया। इस विशिष्ट दिवस पर आयोजित समारोहों के माध्यम से केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने एक दूसरे की बराबरी की टक्कर दी।

जहाँ केंद्रीय गृहमन्त्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा निज़ाम के शासन से तेलंगाना की आज़ादी का जश्न मना रही थी, वहीं तेलंगाना सरकार इस दिवस को "तेलंगाना एकीकरण दिवस" के रूप में मना रही थी तथा इस प्रकार दो विचार धाराओं के बीच सीधा टकराव देखने को मिला रहा था। दोनों ही राजनैतिक संगठन चुनावी जंग की तैयारी करते नजर आ रहे थे। जहाँ एक दल मुनूगोडे विधान सभा सीट के लिये शीघ्र ही होने वाले उप चुनाव को ध्यान में रखे हुये था, वहीं दूसरा दल अगले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अमित शाह ने इस अवसर पर, 17 सितम्बर, 1948 को हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्ति मिलने के दिन को याद किया।
- मु.मंत्री के.सी.आर. ने इस दिन को, "तेलंगाना एकीकरण दिवस" के रूप में मनाया।
- दोनों ओर से झण्डा रोहण में धुआंधार भाषण हुए, एक दूसरे (भाजपा व टी.आर.एस.) के खिलाफ।
- मु.मंत्री ने आरोप लगाया कि, इस अवसर का उपयोग भाजपा जनता को धर्म व साम्प्रदायिकता पर बांटने के लिए कर रही है। केवल आगामी उपचुनाव व बाद में अगले वर्ष तेलंगाना विधानसभा को देखते हुए ही भाजपा "हैदराबाद मुक्ति दिवस" का आयोजन कर रही है। अन्यथा आज़ादी के बाद जूनागढ़ का भी भारत में विलय हुआ, उसे भाजपा समारोह के रूप में क्यों नहीं मना रही।
- अमित शाह ने तेलंगाना की के.सी.आर. सरकार पर व्यंग्य करते हुए कहा कि, वोट बैंक की राजनीति के कारण ही तेलंगाना सरकार हैदराबाद को निज़ाम शासन से मुक्ति मिलने की खुशी के रूप में मनाने से डरती है।

नीतीश-सोनिया मुलाकात

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में

- बिहार के मु.मंत्री नीतीश कुमार ने आगामी 25 नवम्बर को या अगले सप्ताह में कभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात का समय मांगा है, वे उन्हें केजरीवाल, के.सी.आर. और ममता बनर्जी से मतभेद खत्म करने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे।

विपक्ष को एकजुट करने के लिए भाजपा का साथ छोड़ दिया था, ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रदेश अध्यक्ष और ए.आई.सी.सी. सदस्य बनाने का अधिकार सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया

राजस्थान के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव पारित हुआ पी.सी.सी. की बैठक में

जयपुर, 17 सितम्बर (का.प्र.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सदस्य बने नेताओं की पहली बैठक में प्रदेश रिटर्निंग अधिकारी राजेंद्र कुंपावत के सामने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा राजस्थान से बनने वाले एआईसीसी सदस्यों के चुनाव का अधिकार सर्वसम्मति से दे दिया गया। इसके बाद कुंपावत बैठक से बाहर आ गए, लेकिन बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी सदस्यों से राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर मंशा जानी, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी राय सहमति के रूप में दी।

हालांकि अशोक गहलोत की ओर से इस बारे में सिर्फ राय जानी गई थी, यह प्रस्ताव नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बैठक के बाद मंत्रियों से यह कहलाया गया कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी अजय माकन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पीआरओ की अध्यक्षता में हुई पीसीसी सदस्यों की बैठक में सिर्फ एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष तथा एआईसीसी डेलीगेट्स चुनने का सर्वसम्मति से अधिकार दिया गया है। इसी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी मंशा है कि हमारे नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सभी सदस्यों की मंशा तो रही है, लेकिन किसी तरह का प्रस्ताव नहीं लाया गया है।

इससे पहले, नए बनाए गए पीसीसी सदस्यों की शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष और एआईसीसी सदस्यों के निर्वाचन का फैसला लेने का अधिकार हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के बाद प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर- पीआरओ बैठक से चले गए। यही प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाएगा।

पीआरओ के जाने के बाद गहलोत ने बैठक में कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, इस पर सभी अपनी राय रखें। गहलोत ने बैठक में मौजूद लोगों से राहुल को अध्यक्ष बनाए जाने पर राय जानी तो सबने हाथ खड़े करके समर्थन किया। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर के जाने के बाद रखा गया। ऐसे में यह प्रस्ताव नहीं माना जा सकता, यह सिर्फ सदस्यों की भावना

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पर एक अनावश्यक विवाद खड़ा हुआ पी.सी.सी. की बैठक के बाद, जब कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने बैठक से बाहर आकर कहा कि, बैठक में यह प्रस्ताव भी "पारित" हुआ पी.सी.सी. सदस्यों की तरफ से कि, राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाये।
- विवाद का जन्म तब हुआ, जब बैठक से प्रदेश रिटर्निंग ऑफीसर के जाने के बाद मु.मंत्री ने, राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये जाने के बारे में सभी सदस्यों की "मंशा" जानने का प्रयास किया, सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर अपनी मंशा का इज़हार किया।
- पर मंशा व्यक्त करना व अधिकृत प्रस्ताव पारित करने में स्वाभाविक ही है, भारी अंतर है।
- बैठक के बाद राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने भी बैठक में एक प्रस्ताव पारित होने की पुष्टि की।

'भारत जोड़ो यात्रा से कोई समस्या नहीं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। सी.पी.आई. (एम) अर्थात माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कुछ पार्टी नेताओं द्वारा किये गये उन ट्वीट्स को खारिज कर दिया है, जिनमें इस बात

- कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा माकपा शासित केरल में प्रवेश कर गई है, जहां वह 18 दिन रहेगी हालांकि माकपा का कहना है कि, उन्हें कांग्रेस की इस यात्रा से कोई समस्या नहीं है, वे इसका विरोध नहीं करेंगे।

पर आपत्ति की गई थी कि कांग्रेस की "भारत जोड़ो यात्रा" कम्यूनिस्ट शासित केरल में 18 दिन तथा भाजपा-शासित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)